an>

Title: Need to constitute a relief fund for farmers and enhance the support prices of cereals.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो मैं यहीं से बोलूं। आज देश में मोटा अनाज पैदा करने वाला किसान बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, जैसे जो किसान धान और गेहूं का उत्पादन करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति आज के दिन बहुत ही खराब है। इसका कारण यह है कि एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी कम है और दूसरे जो सरकारी दर है, उस पर भी किसान के धान या गेहूं की खरीद नहीं की जाती। खासकर बिहार की स्थिति तो और भी दयनीय है जहां कि सरकार धान और गेहूं के खरीदने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए पिछले साल भी यह काफी विफल हुई है। मेरे अपने जिले औरंगाबाद जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, दो जिले औरंगाबाद और गया हैं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। पिछले साल वहां के किसानों का सौ करोड़ रुपया बकाया ह, इसी तरह से गया जिले के किसानों का भी एक अरब से ज्यादा रुपया बकाया है और रोहताश जिले में करीब 37 करोड़ रुपए किसानों के धान के बकाया हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपने जो विषय enhance the support prices of cereals दिया था, उसके अनुरूप नहीं बोल रहे हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि एमएसपी की दर बढ़ाई जाए क्योंकि पिछले कई वर्षों से यह संशोधित नहीं हुई है। इसके अलावा शत प्रतिशत खरीद की गारंटी की जाए। मैं सुझाव देते हुए यह मांग भी करना चाहता हूं कि जिस तरह से गन्ना किसानों का गन्ना मिलो के माध्यम से खरीदा जाता है। गन्ना किसान अपना गन्ना मिलों तक पहुंचा देते हैं। उन्हें एक पर्ची मिल जाती है और उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यही व्यवस्था धान और गेहूं के लिए भी होनी चाहिए। हमारे यहां हजारों-हजार चावल मिल हैं। अगर किसान अपना धान वहां पहुंचा दें और उन्हें पर्ची मिल जाए और उनका पैसा उनके बैंक एकाउंट में चला जाए जब यह व्यवस्था लागू होगी, तब किसानों को फायदा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष :

श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।